International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

सुशासन : जिला प्रशासन सीकर जिले के संदर्भ में प्रभावशीलता का मूल्यांकन

[1]प्रदीप शर्मा, [2]डॉ. मंजु लाडला
[1]शोधार्थी , पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
[2]आचार्य , राजनीति विज्ञान विभाग ,श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर
Email: rps.india1947@gmail.com

सारांश (Abstract)

सुशासन समकालीन लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका संबंध प्रशासनिक प्रभावशीलता, समता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा विधि के शासन से है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राजस्थान के सीकर जिले में 2015 से 2025 की अवधि के दौरान सुशासन की स्थिति का जिला-स्तरीय मूल्यांकन करना तथा उसके सामयिक और स्तंभ-आधारित परिवर्तनशील स्वरूप का विश्लेषण करना है। अध्ययन में 15 चयनित संकेतकों के आधार पर प्रभावशीलता, समता एवं विधि का शासन—इन तीन प्रमुख शासन-स्तंभों के अंतर्गत सुशासन की स्थिति का परीक्षण किया गया है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें जिला-स्तरीय द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करते हुए न्यूनतम–अधिकतम सामान्यीकरण तकनीक तथा समान-भार पद्धति द्वारा समग्र सुशासन सूचकांक (CGI) एवं स्तंभ-आधारित सूचकांक निर्मित किए गए हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि सीकर जिले में समग्र सुशासन सूचकांक 2015 के 0.37 से बढ़कर 2020 में 0.66 तथा 2025 में 0.68 हो गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि में सुशासन की स्थिति में समग्र सुधार हुआ है। आर्थिक, अवसंरचनात्मक, सेवा-प्रदाय तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित हुई, जबकि समता-संबंधी संकेतकों में भी स्पष्ट उन्नयन दर्ज किया गया। इसके विपरीत, विधि के शासन से संबद्ध संकेतकों, विशेषतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हिंसा एवं सुरक्षा-संबंधी आयामों में गिरावट पाई गई, जिसके कारण शासन-प्रदर्शन का विकास असंतुलित रूप में उभरकर सामने आया। स्तंभ-आधारित विश्लेषण में प्रभावशीलता और समता में उल्लेखनीय वृद्धि के विपरीत 2025 में विधि के शासन सूचकांक में तीव्र गिरावट दर्ज हुई। अतः अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि सीकर जिले की सुशासन स्थिति “प्रगतिशील किन्तु असंतुलित” है, जिसके संतुलित एवं समावेशी सुदृढ़ीकरण हेतु विधि के शासन, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायिक-प्रशासनिक उत्तरदायित्व को विशेष प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मुख्य शब्द :- सुशासन, समग्र सुशासन सूचकांक (CGI), प्रभावशीलता, समता एवं समावेशन, विधि का शासन, सामयिक, अवसंरचनात्मक ।

प्रस्तावना (Introduction)

समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शासन की गुणवत्ता को सामाजिक विकास, नागरिक विश्वास और प्रशासनिक वैधता का प्रमुख आधार माना जाता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में केवल सरकार का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुखी होना अनिवार्य हो गया है। इसी संदर्भ में 'सुशासन' (Good Governance) की अवधारणा एक केंद्रीय प्रशासनिक विमर्श के रूप में

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

उभरकर सामने आई है। भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में, जहाँ शासन की वास्तविक पहुँच आम नागरिक तक जिला स्तर के माध्यम से होती है, वहाँ जिला प्रशासन की भूमिका सुशासन को व्यावहारिक रूप देने में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है (विश्व बैंक, 1992। सुशासन सतत विकास एवं प्रभावी लोक प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, विशेषकर जिला स्तर पर, जहाँ शासन की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिणामों पर पड़ता हैं, वहाँ सुशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है । सुशासन बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें अभिव्यक्ति एवं उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारी प्रभावशीलता, विनियामक गुणवत्ता, विधि का शासन तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे आयाम सम्मिलित होते हैं। ये सभी आयाम सामूहिक रूप से उस संस्थागत वातावरण का निर्माण करते हैं, जो विकास तथा प्रशासनिक सेवाओं के प्रति नागरिक संतुष्टि के लिए आवश्यक है (अजमत एवं कॉगहिल, 2005; चीएन एवं थानह, 2022)।

भारतीय प्रशासनिक ढाँचे में जिला प्रशासन, शासन और समाज के बीच सबसे महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में संचालित प्रशासनिक तंत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन, कानून-व्यवस्था के संधारण, लोक सेवाओं की आपूर्ति, राजस्व प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन जैसे बहुआयामी दायित्वों का निर्वहन करता है (भारत सरकार, 2011)। सीकर जिले के प्रशासनिक संदर्भ में शासन-प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि स्थानीय सरकारें सेवा वितरण, संसाधन प्रबंधन तथा जनविश्वास बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं (आचार्य, 2018;जमील एट अल., 2019)। प्रभावी शासन के लिए प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता अनिवार्य तत्व हैं। ये तत्व न केवल राजनीतिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि समग्र विकास की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करते हैं। (अमीन एट अल., 2024; रोएहल एवं हैनसेन, 2024)।

जिला-स्तरीय शासन की प्रभावशीलता प्रायः तकनीकी क्षमता और प्रशासनिक मानकों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती है। इसमें विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता, नैतिक मानकों का अनुपालन तथा लोकसेवकों की व्यावसायिक दक्षता जैसे तत्व सम्मिलित हैं (ओचिएंग एट अल., 2016; चीएन एवं थानह, 2022)। यदि शासन के किसी भी आयाम में कमी रह जाती है, तो सेवा वितरण की गुणवत्ता तथा सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अतः शासन सुधारों को स्थानीय प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के साथ समन्वित करना आवश्यक है (अमीन एट अल., 2024; अजमत एवं कॉगहिल, 2005)। साथ ही, प्रशासन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने दक्षता में वृद्धि की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं, किंतु इसके साथ-साथ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे मूलभूत स्तंभों का संतुलन बनाए रखना भी अनिवार्य है। (रोएहल एवं हैनसेन, 2024; जमील एट अल., 2019)।

राजस्थान राज्य का सीकर जिला प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह जिला शेखावाटी अंचल का हिस्सा होने के कारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशिष्टः पहचान रखता है। साथ ही, सीकर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु इसके समानांतर कृषि संकट, ग्रामीण बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता तथा प्रशासनिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों भी विद्यमान है (राजस्थान सरकार, 2020)। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि जिला प्रशासन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हुए सुशासन के सिद्धांतों को लागू कर रहा है, इसका सम्यक् मूल्यांकन किया जाएँ। इस अध्ययन की प्रासंगिकता इस

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

तथ्य में निहित है कि यह जिला स्तर पर सुशासन की व्यावहारिक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अधिकांश प्रशासनिक अध्ययन नीति स्तर पर केंद्रित रहते हैं, जबकि यह शोध जमीनी स्तर पर प्रशासनिक क्रियान्वयन और उसके सामाजिक प्रभावों को समझने का प्रयास करता हैं । अतः सीकर जिले के प्रशासनिक संदर्भ में शासन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एक समग्र रूपरेखा के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है, जिसमें संस्थागत प्रदर्शन, नागरिक सहभागिता, उत्तरदायित्व तंत्र तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक सुधारों को समाहित किया जाए। (अजमत एवं कॉगहिल, 2005; अरिस्टोवनिक एट अल., 2022)।

सुशासन: सैद्धान्तिक रूपरेखा :-

सुशासन की अवधारणा प्रशासनिक सिद्धांतों के विकास की एक महत्त्वपूर्ण परिणति मानी जाती है। पारंपरिक शासन व्यवस्था, जो मुख्यतः नियंत्रण, आदेश और नियमों पर आधारित थी यदपि यह आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ सिद्ध हुई। इसी पृष्ठभूमि में सुशासन की अवधारणा विकसित हुई, जो शासन को केवल सता-प्रयोग का माध्यम न मानकर नागरिकों के कल्याण और सहभागिता से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखती है। सुशासन को सैद्धान्तिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह **"विकास हेतु किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग की विधि"** को निरूपित करता है। (विश्व बैंक, 1992) 1990 के दशक में यह अवधारणा व्यापक रूप से प्रचलित हुई और इसने पारंपरिक नौकरशाही-आधारित "सरकार" (Government) की संकीर्ण धारणा से हटकर एक व्यापक एवं समावेशी "शासन" (Governance) प्रतिमान की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया। इस प्रतिमान में विकास प्रक्रियाओं में राज्य, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज की सहयोगात्मक भूमिकाओं को मान्यता प्रदान की गई है। (UNESCAP, 2009) यह परिवर्तन संस्थागत गुणवत्ता, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास परिणामों पर विशेष बल देता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने सुशासन को एक व्यापक अवधारणा के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि **" यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य की शक्ति का प्रयोग आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार किया जाता है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे और शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो"** (यूएनडीपी, 1997)। इस दृष्टिकोण में सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी अपने भीतर समाहित करता है। अतः सुशासन को एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य और समाज के बीच विश्वास की नींव को मजबूत करता है।(सेन, 1999)

सुशासन की यह रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त आठ प्रमुख तत्त्वों पर आधारित है (UNESCAP, 2009; विश्व बैंक, 1992)। जिनमें **सहभागिता** (Participation) निर्णय-प्रक्रिया में सभी हितधारकों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करती है; **विधि का शासन** (Rule of Law) न्यायसंगतता एवं अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है; तथा **पारदर्शिता** (Transparency) सूचना की मुक्त एवं सुगम उपलब्धता को प्रोत्साहित करती है। **प्रत्युत्तरदायित्व** (Responsiveness) यह अपेक्षा करता है कि संस्थाएँ नागरिक आवश्यकताओं का समयबद्ध समाधान करें, जबकि **सहमति-आधारित दृष्टिकोण**

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

(Consensus-Oriented Approach) विविध सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। **समता एवं समावेशन** (Equity and Inclusiveness) यह सुनिश्चित करते हैं कि हाशिए पर स्थित वर्ग मुख्यधारा से वंचित न रहें, तथा **प्रभावशीलता एवं दक्षता** (Effectiveness and Efficiency) संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर बल देती हैं। अंततः **उत्तरदायित्व** (Accountability) सार्वजनिक संस्थाओं को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। सामूहिक रूप से ये सभी तत्त्व सतत मानव विकास, गरीबी उन्मूलन तथा जीवन-स्तर में सुधार को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखते हैं (अजमत एवं कॉगहिल, 2005; चीएन एवं थानह, 2022)।

अनुसंधान उद्देश्य (Research Objectives)

जिला स्तर पर सुशासन की गुणवत्ता का आँकलन विकास की दिशा, प्रशासनिक क्षमता तथा सामाजिक विश्वास की स्थिति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। 2015–2025 की अवधि में सीकर जिले में प्रशासनिक सुधारों, अवसंरचनात्मक विस्तार एवं सामाजिक संकेतकों में हुए परिवर्तनों ने शासन-प्रदर्शन की प्रकृति को पुनर्परिभाषित किया है। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं परिवर्तनों का समग्र विश्लेषण करते हुए बहुआयामी सुशासन के स्वरूप, प्रवृत्तियों तथा नीतिगत निहितार्थों का परीक्षण करने का उद्देश्य रखता है। इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित पांच उद्देश्यों का निर्धारण किया गया ।

1. वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में समग्र सुशासन सूचकांक के आधार पर सीकर जिले के बहुआयामी शासन-प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
2. प्रभावशीलता, समता-समावेशन तथा विधि के शासन जैसे प्रमुख स्तंभों की तुलनात्मक प्रगति का विश्लेषण कर प्रशासनिक सुदृढ़ता एवं कमजोरी के आयामों की पहचान करना।
3. अवसंरचना, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय समावेशन के सुधारों का समग्र सुशासन सूचकांक पर प्रभाव परीक्षण करना।
4. कानून-व्यवस्था एवं लैंगिक सुरक्षा संकेतकों का शासन-गुणवत्ता पर प्रभाव आकलित कर सामाजिक सुरक्षा आयाम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना।
5. सामयिक विश्लेषण के माध्यम से 2015 से 2025 तक शासन-प्रदर्शन की प्रवृत्तियों की पहचान करना ।

शोध कार्यप्रणाली (Methodology)

यह अध्ययन राजस्थान राज्य के सीकर जिले पर केंद्रित है। शोध का उद्देश्य सुशासन का जिला स्तर पर मूल्यांकन एवं इसका सामयिक विश्लेषण कर तुलनात्मक एवं प्रवृत्ति-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा समग्र सूचकांक पद्धति पर आधारित है। शोध रूपरेखा तीन स्तरों में विभाजित की गई हैं 1.**संकेतक-आधारित मापन** 2.**समग्र सूचकांक निर्माण** 3. **स्तंभ-आधारित तुलनात्मक विश्लेषण एवं प्रवृत्ति परीक्षण**

आँकड़ा स्रोत (Data Sources) :- अध्ययन में प्रयुक्त सभी 15 संकेतक जिला-स्तरीय आधिकारिक द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं, जिनमें प्रमुखतः सतत विकास लक्ष्य स्थिति रिपोर्ट 2020 , 2025, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स रिपोर्ट 2025, जिला सांख्यिकी प्रकाशन, स्वास्थ्य, अपराध एवं अवसंरचना से संबंधित विभागीय अभिलेख, जनगणना प्रतिवेदन 2011 एवं अन्य सरकारी विभागों एवं प्रकाशित अभिलेखों से आँकड़ों का संकलन किया गया । डेटा का चयन इस आधार पर किया गया कि

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

वह समय-श्रृंखला उपलब्धता, तुलनीयता तथा शासन-आयामों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करे। फिर भी अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसके कारण कुछ सीमाएँ विद्यमान हो सकती है।

संकेतक चयन एवं स्तंभ-मैपिंग (Indicator Selection & Pillar Mapping):- अध्ययन के लिए कुल 15 संकेतकों का चयन किया गया संकेतकों के चयन के समय उनकी सामायिक उपलब्धता , तुलनीयता एवं सुशासन के आयामों में प्रतिनिधित्वता को केंद्र में रखा गया हैं

तालिका - 1. अध्ययन के लिए चयनित सुशासन स्तम्भ एवं संकेतक

सुशासन स्तंभ	**अध्ययन के लिए चयनित संकेतक**
प्रभावशीलता (Effectiveness)	DDP वृद्धि, संस्थागत प्रसव, TB (प्रतिलोम), सड़क लंबाई, ग्राम संपर्क, एटीएम
समता (Equity)	स्वच्छ ईंधन, बालिका शौचालय, जन्म-लिंग अनुपात, महिला प्रॉक्सी, वनावरण
विधि का शासन (Rule of Law)	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (प्रतिलोम), हिंसा (प्रतिलोम), हत्या (प्रतिलोम), सड़क दुर्घटना मृत्यु (प्रतिलोम)

आँकड़ा विश्लेषण (Data Analysis) :- अध्ययन क्षेत्र में सुशासन की स्थिति का सामयिक विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए चयनित 15 संकेतकों के आधार पर (न्यूनतम – अधिकतम) सामान्यीकरण तकनीक एवं समान-भार पद्धति का उपयोग करते हुए समग्र सुशासन सूचकांक निर्मित किया गया। अपराध एवं मृत्यु-संबंधी संकेतकों हेतु प्रतिलोम सामान्यीकरण लागू किया गया। शासन के विभिन्न आयामों प्रभावशीलता, समता एवं विधि का शासन के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए स्तम्भ आधारित औसत सूचकांक निकालकर विश्लेषण किया गया ।

(i) **सामान्यीकरण तकनीक (Normalization Technique)**

अध्ययन के लिए चयनित सभी 15 संकेतकों की माप इकाइयाँ भिन्न - भिन्न हैं, अतः सभी के बीच समान तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम - अधिकतम सामान्यकरण तकनीकी अपनाई गई । इस तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संकेतक को **0 से 1 के समान स्केल** पर परिवर्तित किया जाता है। जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक संकेतकों के लिए भिन्न - भिन्न सूत्रों का प्रयोग किया गया हैं ।

(क) सकारात्मक संकेतक (उच्चतम = बेहतर) = X_norm = (X − X_min) / (X_max − X_min)

(ख) प्रतिलोम संकेतक (न्यूनतम = बेहतर) = X_norm = (X_max − X) / (X_max − X_min)

यहाँ : - X_norm = संकेतक का सामान्यीकृत मान (0 से 1 के बीच)

X = किसी वर्ष का वास्तविक मान

X_{min} = उस संकेतक का न्यूनतम मान

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

X_{max}= उस संकेतक का अधिकतम मान

इस प्रक्रिया से प्रत्येक संकेतक का मान 0 से 1 के मध्य स्केल पर परिवर्तित किया गया।

(ii) समग्र सुशासन सूचकांक (Composite Good Governance Index – CGI)

GGI = (1/n) ∑_{i=1}^{n} X_i^{norm}

जहाँ:- n = कुल संकेतक

(X_i^{norm}) = सामान्यीकृत मान

(iii) स्तंभ-आधारित सूचकांक (Pillar-wise Governance Index)

Pillar Index = (1/k) ∑ X_pillar

जहाँ :- **X_pillar** = उस शासन-स्तंभ के अंतर्गत आने वाले संकेतकों के सामान्यीकृत (Normalized) मान

k = उस शासन-स्तंभ में सम्मिलित संकेतकों की संख्या

सीकर जिले में सुशासन की स्थिति एवं इसका सामयिक विश्लेषण:-

सीकर जिले में सुशासन की स्थिति के आँकलन हेतु चयनित 15 संकेतकों के आँकड़ों को वर्ष 2015, 2020 तथा 2025 के संदर्भ में संकलित कर तालिका में प्रस्तुत किया गया है। तालिका में प्रत्येक चर/संकेतक को संबंधित शासन-स्तंभ के आधार पर व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है। साथ ही प्रत्येक संकेतक के लिए प्रभाव की दिशा (अधिक बेहतर अथवा कम बेहतर) तथा सामान्यीकरण के प्रकार को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, जिससे संकेतकों का व्यवस्थित वर्गीकरण एवं तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो सके।

तालिका – 2. सीकर जिला वर्षवार संकेतक रूपरेखा

क्र. सं.	चर / संकेतक	सुशासन स्तंभ	प्रभाव की दिशा	सामान्यीकरण प्रकार	2015	2020	2025
1.	प्रति व्यक्ति DDP की वार्षिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्य 2011–12)	प्रभावशीलता (आर्थिक शासन)	अधिक बेहतर	सकारात्मक	0.31	3.97	5.50
2.	संस्थागत प्रसव (%)	प्रभावशीलता (सेवा वितरण – स्वास्थ्य)	अधिक बेहतर	सकारात्मक	92.00	99.67	99.80
3.	टीबी अधिसूचना दर (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	प्रभावशीलता (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	कम बेहतर	प्रतिलोम	125.00	184.00	165.00

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

4.	स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार (%)	समता एवं कल्याण	अधिक बेहतर	सकारात्मक	42.80	58.40	58.40
5.	बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय वाले विद्यालयों का अनुपात (%)	समता एवं समावेशन	अधिक बेहतर	सकारात्मक	98.76	94.63	97.96
6.	जन्म के समय लिंग अनुपात	समता एवं सामाजिक न्याय	अधिक बेहतर	सकारात्मक	858	1061	1061
7.	महिला कार्य-भागीदारी (कल्याण संकेतकों के माध्यम से प्रॉक्सी)	समता एवं सहभागिता	अधिक बेहतर	सकारात्मक	जनगणना-2011 आधार	प्रॉक्सी	प्रॉक्सी
8.	महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर (प्रति 1,00,000 महिला जनसंख्या)	विधि का शासन एवं सुरक्षा	कम बेहतर	प्रतिलोम	49.00	92.36	130.25
9.	महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता/हिंसा (प्रति लाख महिला)	विधि का शासन एवं मानवाधिकार	कम बेहतर	प्रतिलोम	30.92	46.75	73.15
10.	हत्या / जानबूझकर की गई हत्या (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	विधि का शासन एवं सुरक्षा	कम बेहतर	प्रतिलोम	1.83	1.89	3.34
11.	सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु दर (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	विनियामक गुणवत्ता एवं सुरक्षा	कम बेहतर	प्रतिलोम	34.51	14.79	24.12
12.	प्रति 100 वर्ग किमी सड़क लंबाई	प्रभावशीलता (अवसंरचना शासन)	अधिक बेहतर	सकारात्मक	60.48	74.45	86.79
13.	सर्व-मौसमी सड़कों से जुड़े ग्राम (%)	प्रभावशीलता एवं पहुँच	अधिक बेहतर	सकारात्मक	89.59	97.50	98.47
14.	प्रति 1,00,000 जनसंख्या एटीएम	पारदर्शिता एवं वित्तीय समावेशन	अधिक बेहतर	सकारात्मक	6.22	11.69	12.00
15.	कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण	सततता (पर्यावरणीय	अधिक बेहतर	सकारात्मक	2.50	2.61	2.83

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

	(%)	शासन)					

स्रोत :- सतत विकास लक्ष्य स्थिति रिपोर्ट 2020 , 2025;

नोट - जनगणना 2011 के पश्चात जिला-स्तर पर महिला कार्य-भागीदारी के सतत वार्षिक आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण इसे एक निहित शासन-परिणाम (Implicit Governance Outcome) के रूप में ग्रहण किया गया है। अतः लैंगिक सहभागिता को कल्याण, अवसंरचना, सेवा-प्रदाय तथा आर्थिक शासन से संबंधित संकेतकों के माध्यम से परोक्ष रूप से परिलक्षित किया गया है।

तालिका – 3. चयनित संकेतकों का सामान्यीकृत मान (0–1 स्केल)

क्र. सं.	**संकेतक**	**2015**	**2020**	**2025**	**क्र. सं.**	**संकेतक**	**2015**	**2020**	**2025**
1	प्रति व्यक्ति DDP वृद्धि	0.00	0.71	1.00	9	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (प्रतिलोम)	1.00	0.63	0.00
2	संस्थागत प्रसव	0.00	0.98	1.00	10	हत्या दर (प्रतिलोम)	1.00	0.96	0.00
3	टीबी अधिसूचना दर (प्रतिलोम)	1.00	0.00	0.32	11	सड़क दुर्घटना मृत्यु (प्रतिलोम)	0.00	1.00	0.53
4	स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन	0.00	1.00	1.00	12	सड़क लंबाई	0.00	0.53	1.00
5	विद्यालयों में बालिकाओं हेतु शौचालय	1.00	0.00	0.81	13	ग्राम सड़क संपर्क	0.00	0.89	1.00
6	जन्म के समय लिंग अनुपात	0.00	1.00	1.00	14	प्रति जनसंख्या एटीएम	0.00	0.95	1.00
7	महिला सहभागिता (प्रॉक्सी)	0.50	0.50	0.50	15	वनावरण	0.00	0.33	1.00
8	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (प्रतिलोम)	1.00	0.47	0.00					

तालिका - 4. **समग्र सुशासन सूचकांक (समान-भार पद्धति)**

वर्ष	**सामान्यीकृत मानों का योग**	**समग्र सुशासन सूचकांक (CGI)**
2015	5.50	0.37
2020	9.95	0.66
2025	10.16	0.68

तालिका 3. (चयनित संकेतकों का सामान्यीकृत मान) में 15 चयनित संकेतकों को 0–1 स्केल पर सामान्यीकृत कर विभिन्न वर्षों (2015, 2020 एवं 2025) के लिए तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है। सामान्यीकरण की इस प्रक्रिया में प्रत्येक संकेतक के लिए **"अधिक मान - बेहतर स्थिति"** तथा

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

"प्रतिलोम संकेतकों" के लिए **"कम मान - बेहतर स्थिति"** के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे सभी संकेतकों को एक समान तुलनीय आधार पर लाया जा सके।

संकेतक-आधारित प्रवृत्तियों का विश्लेषण:-

सामान्यीकृत मानों से स्पष्ट होता है कि सीकर जिले में सुशासन के विभिन्न आयामों में समय के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं—

- **आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक संकेतक** जैसे प्रति व्यक्ति DDP वृद्धि (0.00 से 1.00), सड़क लंबाई (0.00 से 1.00), ग्राम सड़क संपर्क (0.00 से 1.00) तथा प्रति जनसंख्या एटीएम (0.00 से 1.00) में निरंतर सुधार देखा गया है। यह प्रशासनिक दक्षता एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर संकेत करता है।
- **सामाजिक विकास एवं सेवा वितरण के संकेतक**—संस्थागत प्रसव, स्वच्छ ईंधन उपयोग तथा बालिकाओं हेतु शौचालय—में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, यद्यपि कुछ संकेतकों (जैसे विद्यालय शौचालय) में मध्य अवधि (2020) में गिरावट के बाद पुनः सुधार परिलक्षित होता है, जो नीतिगत असंतुलन या क्रियान्वयन की अस्थिरता को दर्शाता है।
- **स्वास्थ्य संकेतक** के रूप में टीबी अधिसूचना दर (प्रतिलोम) में 2015 (1.00) से 2020 (0.00) तक गिरावट और 2025 (0.32) में आंशिक सुधार देखा गया है, जो स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों एवं सुधारात्मक प्रयासों दोनों को प्रतिबिंबित करता है।
- **लैंगिक एवं सामाजिक न्याय से संबंधित संकेतक**—महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं हिंसा—में 2015 (1.00) से 2025 (0.00) तक स्पष्ट गिरावट पाई गई है, जो कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय है।
- **पर्यावरणीय संकेतक** जैसे वनावरण में 2015 (0.00) से 2025 (1.00) तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दीर्घकालिक सतत विकास की दिशा में सकारात्मक प्रवृत्ति को इंगित करता है।
- **महिला सहभागिता (प्रॉक्सी)** का मान तीनों वर्षों में स्थिर (0.50) बना हुआ है, जो इस क्षेत्र में संरचनात्मक ठहराव एवं नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

सामयिक प्रवृति का विश्लेषण :-

तालिका 4. (समग्र सुशासन सूचकांक) से स्पष्ट होता है कि सीकर जिले में 2015 से 2025 के मध्य सुशासन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। समग्र सुशासन सूचकांक (CGI) 2015 के 0.37 से बढ़कर 2020 में 0.66 तथा 2025 में 0.68 हो गया। 2015–2020 के दौरान तीव्र वृद्धि प्रशासनिक एवं अवसंरचनात्मक सुधार को दर्शाती है, जबकि 2020–2025 में वृद्धि की धीमी गति सुशासन के स्थिरीकरण चरण की ओर संकेत करती है। यद्यपि अवसंरचना एवं आर्थिक संकेतकों में और सुदृढ़ता आई, तथापि कानून एवं व्यवस्था से संबंधित संकेतकों (विशेषकर अपराध दर) में गिरावट ने समग्र वृद्धि की गति को प्रभावित किया।

स्तंभ-आधारित सुशासन सूचकांक विश्लेषण :-

International Journal of Advance Interdisciplinary Research
Vol. 02 Issue 1, Part A (Jan-March) 2026, pp. 266-278, e-ISSN: 3107-913X
DOI: https://doi.org/10.66095/ijair.2026.v2.i1.a.17

स्तंभ-आधारित सुशासन सूचकांक विश्लेषण के अंतर्गत सीकर जिले में सुशासन की स्थिति के मूल्यांकन हेतु चयनित 15 संकेतकों को तीन प्रमुख शासन स्तंभों—प्रभावशीलता, समता एवं विधि का शासन—में वर्गीकृत किया गया। तत्पश्चात प्रत्येक स्तंभ के लिए समग्र सूचकांक का निर्माण कर 2015, 2020 एवं 2025 के वर्षों में स्तंभवार सुशासन की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - 5. स्तंभ-वार औसत स्कोर (0 – 1)

वर्ष	प्रभावशीलता	समता	विधि का शासन
2015	0.167	0.300	0.750
2020	0.677	0.566	0.765
2025	0.887	0.862	0.132

तालिका में स्तंभ-आधारित सुशासन सूचकांक विश्लेषण से स्पष्ट होता है की सुशासन की स्थिति में सामयिक परिवर्तन हुए हैं , जिनमें -

- **प्रभावशीलता** में 2015 से 2025 के मध्य अत्यधिक वृद्धि (0.167 - 0.887) स्पष्ट है, जो आर्थिक प्रदर्शन, अवसंरचना विस्तार, सेवा-प्रदाय दक्षता तथा वित्तीय पहुँच में सुधार को दर्शाती है।
- **समता** में भी उल्लेखनीय वृद्धि (0.300 - 0.862) परिलक्षित होती है, जो स्वच्छ ईंधन उपयोग, लैंगिक सुविधाओं, लिंग अनुपात सुधार तथा पर्यावरणीय संकेतकों में प्रगति का संकेत देती है।
- इसके विपरीत, **विधि का शासन** 2025 में तीव्र गिरावट (0.765 - 0.132) प्रदर्शित करता है, जो अपराध एवं सुरक्षा-संबंधी संकेतकों में अवनति के कारण **"न्याय एवं सुरक्षा"** आयाम पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

आलेख : सीकर जिला : स्तंभ-आधारित सुशासन सूचकांक

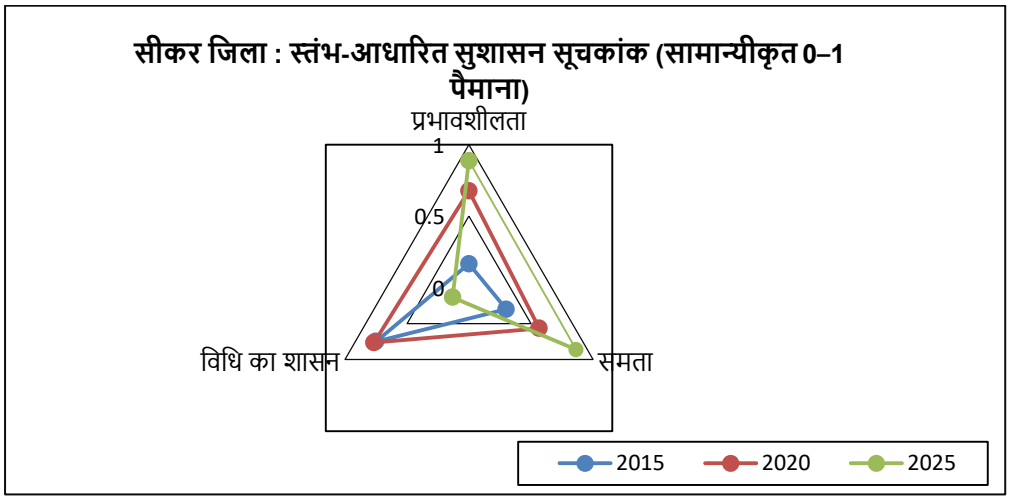

निष्कर्ष (Conclusion):

प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीकर जिले में 2015 से 2025 की अवधि के दौरान सुशासन की स्थिति में समग्र रूप से उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित होता है, किन्तु यह

सुधार संतुलित नहीं है। समग्र सुशासन सूचकांक (CGI) में निरंतर वृद्धि प्रशासनिक दक्षता, अवसंरचना विस्तार, सेवा-प्रदाय सुधार तथा वित्तीय समावेशन में प्रगति को दर्शाती है। विशेष रूप से प्रभावशीलता एवं समता के स्तंभों में तीव्र वृद्धि यह संकेत देती है कि विकासात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव क्षेत्र में परिलक्षित हुआ है।

इसके विपरीत, विधि के शासन से संबंधित संकेतकों में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है, जो कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय के आयामों में संरचनात्मक कमजोरियों को इंगित करती है। यह असंतुलन दर्शाता है कि आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ संस्थागत सुदृढ़ता एवं न्यायिक-प्रशासनिक नियंत्रण को समान प्राथमिकता नहीं दी गई।

अतः समग्र रूप से सीकर जिले की सुशासन स्थिति को **"प्रगतिशील किन्तु असंतुलित"** कहा जा सकता है, जहाँ भविष्य में संतुलित एवं समावेशी सुशासन सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से विधि के शासन एवं सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

References:

Acharya, K. K. (2018). Local Governance Restructuring in Nepal: From Government to Governmentality. Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, 12, 37–49.

Aristovnik, A., Murko, E., & Ravšelj, D. (2022). From Neo-Weberian to Hybrid Governance Models in Public Administration: Differences between State and Local Self-Government. Administrative Sciences, 12(1), 26

Chakrabarty, Bidyut., & Kandpal, P. C. (2025). *Public administration in India*. New Delhi: Routledge

Chien, N. B., & Thanh, N. N. (2022). The Impact of Good Governance on the People's Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam. Administrative Sciences, 12(1), 35. https://doi.org/10.3390/admsci12010035Azmat, F., & Coghill, K. (2005). Good governance and market-based reforms: a study of Bangladesh. International Review of Administrative Sciences, 71(4), 625–638.

Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan. (2011). District statistical handbook: Sikar district. Jaipur: Government of Rajasthan.

Finance Commission India(15th FC). (2019). Performance-based incentives for states. Finance Commission India. https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/15th-FC/reports/studies/... [web:190]

Government of Rajasthan. (2020). Sustainable Development Goals (SDG) status report 2020: Rajasthan. Jaipur: Directorate of Economics and Statistics. https://sdg.rajasthan.gov.in/Master/DownloadFile?fileName=Rajasthan%20SDGs%20Index%202020.pdf&Guid=f418d6a6-7a87-4fa1-b4bc-49c236cb21eb

Government of Rajasthan. (2025). Sustainable Development Goals (SDG) status report 2025: Rajasthan. Jaipur: Directorate of Economics and Statistics.

https://sdg.rajasthan.gov.in/Master/DownloadFile?fileName=Rajasthan%20SDGs%20Index%202025.pdf&Guid=bc976fb0-2940-4d9f-a9f9-6f39333ea1b1

Jain, R.B., (2005). Public administration in India: 21st century challenges for good governance. New Delhi: Deep & Deep Publications

Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good Governance and Public Trust: Assessing the Mediating Effect of E-Government in Pakistan. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 17(2), 299–320.

Ministry of Panchayati Raj. (2022-2023). Panchayat Advancement Index (PAI). PIB India. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120320 [web:188]

Ministry of Statistics and Programme Implementation. (Various years). *Statistical year book India*. New Delhi: Government of India.

National Crime Records Bureau. (2025). Crime in India. New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India.

NITI Aayog. (2025). SDG India index and dashboard 2025. New Delhi: Government of India.

Ochieng, R. M., Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B., Brockhaus, M., & Herold, M. (2016). Institutional effectiveness of REDD+ MRV: Countries progress in implementing technical guidelines and good governance requirements. Environmental Science & Policy, 61, 42–52.

Roehl, U. B. U., & Hansen, M. B. (2024). Automated, administrative decision-making and good governance: Synergies, trade-offs, and limits. Public Administration Review, 84(6), 1184–1199.

Sen Amartya. (1999). Development as freedom. New York: Oxford University Press

UNDP.(2023). SDG India Index: Panchayati Raj performance. UNDP SDG Knowledge Hub. https://sdgknowledgehub.undp.org.in/wp-content/uploads/2023/06/Road-Map-2.pdf [web:191]

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2009). What is good governance? United Nations.

Available at: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance

World Bank. (1992). Governance and development. World Bank Publications, Washington, DC

World Bank.(2015-2020). India local government performance data. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/country/india [web:187][web:193]

World Resources Institute (WRI). (2010-2020). Local governance performance indicators. World Resources Institute Data Portal. https://www.wri.org/data [web:182][web:185]